लोगों को प्रोत्साहित करना और बंदूक छोड़ देने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास आदि शामिल है।

Elections in the Kendriya Bhandar

463. SHRI O.P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether election of the Delegates and Board of Directors have not been held for many years in the Kendriya Bhandar, thereby eroding the democratic character of the Bhandar;

(b) if so, since when these elections have not been held;

(c) the reasons for not holding the elections; and

(d) the steps proposed to be taken to hold elections without any further delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. BALASUB-RAMONIYAN) (a) and (b) The elections of the Delegates in the Kendriya Bhandar were last held in August/September, 1983 and of the Board of Directors in December, 1985. With the retirement of 5 elected Directors from service and with the disqualificaiton of another elected Director on ground of his having interest in the business of the Society, the elected side on the Board of Directors has been reduced from 8 to 2. In order to strengthen the democratic character of the Board, five former Directors, and one Delegate who is the Chairman of the Delegate Forum, are being associated with deliberations of the Board of Directors as 'Invitees' without conferring on them status of Directors and the voting rights.

(c) and (d) The revised bye-laws of Kendriya Bhandar which took effect from 10.4.87 were challenged by some elected Directors/Delegates in the Delhi High Court in 1987. The Writ Petition is pending for final disposal before the High Court. Elections of the Directors/ Delegates are to be conducted under the supervision of the Registrar of Cooperative Societies, who has advised that status-quo may be maintained and that elections be held after final judgement of the High Court is available. Applications have been filed for early hearing of the case.

मध्य प्रदेश में शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम

464. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम (यू०बी०एस०पी०) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के रायगढ़ तथा रायगढ़ जिले के खरसिया शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबों के लिए सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की स्वीकृति से लेकर अब तक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई है;

(ग) राज्य में रायगढ़ जिले के अतिरिक्त अन्य किन-किन शहरों के लिए यह योजना स्वीकृत की गई है; और

(घ) रायगढ़ और खरसिया शहरी क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू): (क) वर्ष 1991 में।

(ख) शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं की स्कीम के तहत व्यय केन्द्र और राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में शेयर किया जाता है। अपेक्षित वर्ष-वार ब्यौरे विवरण-I पर हैं (नीचे देखिए)

(ग) रायगढ़ और खरसिया के अतिरिक्त शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं की स्कीम भोपाल, बेरसिया, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, राजनन्दगांव और मन्दसौर में भी कार्यान्वित की गयी है।

(घ) सूचना विवरण-II में है।